ASSOCHAM IN THE NEWS

31 January, 2017

Dainik Bhaskar (Gwalior)

रॉ मटेरियल का ट्रेंड देखें, फिर मार्केट तलाश करें, इसके बाद लगाएं यूनिट

मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और एसोचैम के सहयोग से हुई एग्री एंड फूड प्रोसेसर कॉन्क्लेव में एक्सपर्ट ने दी जानकारी

AGRO CONCLAVE

सिटी रिपोर्टर • अगर आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं तो इसके लिए संबंधित क्षेत्र में रॉ मटेरियल का ट्रेंड जानना होगा। क्षेत्र की जरूरत क्या है और इंडस्ट्री की जरूरत कैसे पूरी होगी। आप जिस चीज का उत्पादन करना चाहते हैं, पहले वो मार्केट तलाशें फिर यूनिट लगाने की शुरुआत करें। इस तरह फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। यह बात एक्सपर्ट ने कही। सोमवार को मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और द एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया (एसोचैम) के संयुक्त तत्वावधान में एग्रीकल्चर कॉलेज के सभागार में एग्री एंड फूड प्रोसेसर्स कॉन्क्लेव कराई गई। एक्सपर्ट ने कहा कि जो भी यूनिट लगाएं उसका एक्रीडिटेशन जरूर कराएं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा।

लोकल मार्केटिंग प्रोग्राम से मिलेगा फायदा

एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो.एके सिंह ने कहा कि मप्र को 11 एग्रो क्लाइमेट डिवीजन में भी रखा गया है। हमें फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए लोकल मार्केटिंग प्रोग्राम विकसित करना होगा। इससे फायदा यह होगा कि उत्पादन अच्छे स्तर का होगा और उपभोक्ताओं को सही दामों में वस्तु मिल सकेगी।

• एक्सपर्ट ने कहा कि मप्र में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का स्कोप बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए भी है कि मेक इन इंडिया की तर्ज पर मेक इन मप्र अभियान चलाया जा रहा है।

ऑनलाइन पोर्टल से जानें

एसबीआई के एजीएम अवधेश चंद्र सक्सेना ने कहा कि ग्वालियर-चंबल संभाग में एग्रो फूड प्रोसेसिंग में स्मॉल यूनिट ज्यादा हैं। जो लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनकी सहूलियत के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है। इस पर आवेदन करने के साथ वह यह जान सकते हैं कि प्रक्रिया कहां तक पूरी हुई है।

यह भी बताया

क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज (एनएबीसीबी) के एक्सपर्ट उदय कुमार सक्सेना ने कहा कि एनएबीसीबी कई तरह के एक्रीडिटेशन ऑफर करता है। इसमें फूड सेफ्टी मैनेजमेंट, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन सहित अन्य शामिल हैं। जानकारी www.qci.org से ले सकते हैं।

यह भी रखे सुझाव

- एजुकेशन रिसर्च और एक्सटेंशन गतिविधि हों।
- ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती कम करनी होगी।
- विदेशी इन्वेस्टर्स हैं लेकिन ग्रामीण इलाकों में इन्फ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना होगा।
- मंडी स्तर से हमें गुणवत्ता सुधारने की जरूरत है।

प्रदेश में बेहतर संभावनाएं

डिप्टी कमिश्नर विनोद भार्गव ने कहा कि प्रदेश में 6 सरकारी मॉडर्न फूड पार्क और 2 प्राइवेट फूड पार्क हैं। इसलिए यहां फूड प्रोसेसिंग में बेहतर संभावनाएं हैं। साथ ही युवाओं को क्वालिटी टेस्टिंग और नई एग्री टेक्नोलॉजी के जरिए उत्पादन क्षमता भी बढ़ानी होगी।

सरकार ने दिए 2 हजार करोड़

नाबार्ड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर संजीव रमन ने कहा कि केंद्र सरकार ने फूड प्रोसेसिंग के लिए 2 हजार करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसमें वो लोग आवेदन कर सकते हैं, जो फूड पार्क में यूनिट लगाने जा रहे हैं।

• **यह रहे मौजूद:** कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजमाता विजयाराजे सिंधिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो.एके सिंह थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर विनोद भार्गव, एग्रीकल्चर कॉलेज के डीन डॉ.जेपी दीक्षित, ज्वाइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर राजीव जोशी, एसोचैम की डिप्टी डायरेक्टर पूर्णिमा ढींगरा, चेंबर ऑफ कॉमर्स के मानसेवी सचिव डॉ. प्रवीण अग्रवाल, डॉ.एमएम पटेल, डॉ.सुरेश सिंह तोमर, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के उदय कुमार सक्सेना और डॉ.सुधीर चतुर्वेदी मौजूद रहे।

Patrika (Gwalior) 31 January, 2017

एग्री एंड फूड प्रोसेसर्स कॉन्क्लेव आयोजित

मेक इन मप्र से किसानों को होगा फायदा

पत्रिका PLUS रिपोर्टर

ग्वालियर • सोयाबीन उत्पादन के कारण ही मध्यप्रदेश सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ दलहन उत्पादन में भी मध्यप्रदेश अग्रणी है जो कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में एक अहम भूमिका निभा रहा है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। यही कारण ह कि मध्यप्रदेश देश का प्रथम राज्य है जिसके द्वारा विकास का रोड मैप तैयार करते हुए भारत सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम की तर्ज पर मेक इन मध्यप्रदेश कार्यक्रम की शुरूआत की गई। यह बात मुख्य अतिथि के रुप में उपस्थित कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.अनिल कुमार सिंह ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कही। मौका था खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार और राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एग्री एंड फूड प्रोसेसर्स कॉन्क्लेव का। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि डिप्टी कमिश्नर विनोद भार्गव रहे।

किसानों में बढ़ेगा आत्मविश्वास : कार्यक्रम में कुलपति प्रो. सिंह ने आज के आधुनिक परिदृश्य में कृषकों की आय बढ़ाने में खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवधीन की भूमिका के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भारत गांवों का देश है जिसकी अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। यदि समुचित महत्व दिया जाए तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ग्रामीण आत्मनिर्भरता एवं रोजगार सृजन के मामले में परिवर्तन का कारण बन सकता है। गांव-शहर की खाई को पाट सकता है और किसानी के तौर-तरीकों में सुधार लाया जा सकता है। कार्यक्रम में एसोचेम की डिप्टी डायरेक्टर पूर्णिमा ढींगरा ने वर्तमान परिदृश्य में खाद्य प्रसंस्करण की स्थिति की जानकारी देते हुए एसोचेम द्वारा इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। इस बैठक में तकनीकी सेशनल का आयोजन किया गया। जिसमे लगभग 200 से अधिक खाद्य प्रसंस्करण एवं तकनीकी, कृषि एवं उद्यानिकी विकास, बैंकिंग, नाबार्ड, मप्र चेम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री, खाद्य भंडारण चेन से जुड़ी संस्थानों, विभागों एवं उद्यमियों, वैज्ञानिको आदि ने हिस्सा लिया।

Navbharat (Gwalior) 31 January, 2017

खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योगों से जुड़ें किसान : सिंह

ग्वालियर, 30 जनवरी, नभासं. राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, एसोचेम एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विश्वविद्यालय में ''एग्री एण्ड फूड प्रोसेसर्स कोन्क्लेव'' वित्त, तकनीकी एवं बाजार विषय पर एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रो. अनिल कुमार सिंह, कुलपति, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि.,ग्वालियर थे। इसके अतिरिक्त विषिश्ट अतिथि के रूप में विनोद भार्गव, डिप्टी कमिश्नर तथा इस अवसर पर राजीव जोशी, संयुक्त संचालक, डॉ. प्रवीण अग्रवाल, सचिव, म.प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, अवधेशचन्द्र सक्सेना, ए.जी.एम. भारतीय स्टेट बैंक, कु. पूर्णिमा ढींगरा, डिप्टी डायरेक्टर, एसोचेम, नई दिल्ली, 'डॉ. जे.पी. दीक्षित, अधिश्ठाता, कृशि महाविद्यालय, ग्वालियर एंव डॉ.एम.एम.पटेल अयोजन सचिव एंव विभागाध्यक्ष विस्तार षिक्षा विभाग कृशि महाविद्यालय, ग्वालियर उपस्थित थे। कु. पूर्णिमा

ढींगरा, डिप्टी डायरेक्टर, एसोचेम, नई दिल्ली द्वारा वर्तमान परिदृष्य में खाद्य प्रसंस्करण की स्थिति की जानकारी देतु हुये एसोचेम द्वारा इस दिषा में किये जा रहे प्रयासों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई।

मुख्य अतिथि प्रो. अनिल कुमार सिंह ने आज के आधुनिक परिदृष्य में कृषकों की आय बढ़ाने में खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन की भूमिका पर प्रकाष डाला तथा कृशकों को खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योगों से जुड़ने की सलाह दी। आपके द्वारा जानकारी दी गई कि सोयाबीन उत्पादन के कारण मध्यप्रदेष सोया प्रदेष के नाम से भी जाना जाता है इसी के साथ दलहन उत्पादन में भी मध्यप्रदेष अग्रणी है जो कि न्यूट्रीषनल सिक्योरिटी में एक अहम भूमिका निभा रहा है। मध्य प्रदेष षासन द्वारा खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन पर विषेश जोर दिया जा रहा है। यही कारण है कि मध्य प्रदेष देष का प्रथम राज्य है जिसके द्वारा आर्थिक विकास का रोड मेप तैयार करते हुये भारत सरकार के ''मेक इन इंडिया'' कार्यक्रम की तर्ज पर ''मेक इन मध्य प्रदेष'' कार्यक्रम की षुरूआत की गई। उक्त बैठक में तकनीकी सत्र का भी आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता डॉ. सुरेष सिंह तोमर, अधिश्ठाता कृशि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर ने की । इस बैठक में लगभग २०० से अधिक खाद्य प्रसंस्करण एवं तकनीकी, कृशि एवं उद्यानिकी विकास, बैंकिंग, नाबार्ड, म.प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इण्डस्ट्री, खाद्य भंडारण चेन से जुड़ी संस्थाओं, विभागों एवं उद्यमियों, वैज्ञानिक, प्राध्यापक, छात्रों एवं कृशकों ने भागीदारी सुनिश्चित की।

ASSOCHAM IN THE NEWS

Peoples Samachar (Gwalior) **31 January, 2017**

आयोजन ▸▸ एग्री एंड फूड प्रोसेसर्स कोन्क्लेव वित्त तकनीकी एवं बाजार विषय पर कार्यक्रम संपन्न

प्रदेश न्यूट्रीशनल सिक्युरिटी की भूमिका निभा रहा है: प्रो. सिंह

पीपुल्स संवाददाता ● ग्वालियर
editor@peoplessamachar.co.in

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को एग्री एंड फूड प्रोसेसर्स कोन्क्लेव वित्त तकनीकी एवं बाजार विषय पर कार्यक्रम आयोजित हुआ।

विवि के कुलपति प्रो. एके सिंह ने आधुनिक परिदृश्य में कृषकों की आय बढ़ाने में खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन की भूमिका पर प्रकाश डाला तथा कृषकों को खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योगों से जुड़ने की सलाह दी। प्रो. सिंह ने कहा कि सोयाबीन उत्पादन के कारण मध्यप्रदेश सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, दलहन उत्पादन में भी प्रदेश अग्रणी है जो कि न्यूट्रीशनल सिक्युरिटी में एक अहम भूमिका निभा रहा है। प्रदेश शासन द्वारा खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश, देश का प्रथम राज्य है जिसके द्वारा आर्थिक विकास का रोड मैप तैयार करते हुए भारत सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम की तर्ज पर मेक इन मध्यप्रदेश कार्यक्रम की शुरूआत की गई। एसोचेम की डिप्टी डायरेक्टर पूर्णिमा ढींगरा ने वर्तमान परिदृश्य में खाद्य प्रसंस्करण की स्थिति व एसोचेम द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में विनोद भार्गव डिप्टी कमिश्नर ग्वालियर संभाग, राजीव जोशी, संयुक्त संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग म.प्र. शासन, डॉ. प्रवीण अग्रवाल सचिव म.प्र. चेंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री, अवधेशचंद्र सक्सेना एजीएम भारतीय स्टेट बैंक ग्वालियर, डॉ. जेपी दीक्षित अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय ग्वालियर एवं डॉ. एमएम पटेल अयोजन सचिव व विभागाध्यक्ष विस्तार शिक्षा विभाग कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर उपस्थित थे।